कार्यालय मुख्य अभियंता
नोएडा क्षेत्र, नोएडा
33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र
ए-1, सेक्टर-16, नोएडा (गौतमबुद्धनगर)

पत्रांक 1966 मुअ0 (वि0)/नोएडा क्षेत्र/नोएडा दिनांक 25/7/19

कार्यालय ज्ञाप

[illegible]

क्र०	इकाई/संस्था/आवेदक का नाम व पता	स्वीकृति हेतु विद्युत भार	[illegible] का विवरण	कार्य स्थल का पता
1	2	3	4	5
	M/s CBS International Projects Pvt. Ltd., Plot No. 01, Sector-90, Noida, Distt. Gautam Budh Nagar.	10600 KVA (New) (Single Point at 33 KV) Including 2000 KVA for Common Facilities	Commercial	Plot No. 01, Sector-90, Noida, Distt. Gautam Budh Nagar.

[illegible]

इकाई के अनुरोध पर [illegible] केवीए (नया) के विद्युत भार को निम्न चरणों में निर्गत किया जायेगा।

(A) प्रथम चरण – [illegible] केवीए – [illegible]
(B) द्वितीय चरण – [illegible] केवीए – जुलाई, [illegible]
(C) तृतीय चरण – [illegible] केवीए – जुलाई, [illegible]
(D) चतुर्थ चरण – [illegible] केवीए – जुलाई, [illegible]
(E) पंचम चरण – [illegible] केवीए – दिसम्बर, [illegible]

01. [illegible]
02. [illegible]
03. [illegible]
04. [illegible]
05. [illegible]
06. [illegible]
07. [illegible]
08. [illegible]
09. [illegible]
10. [illegible]
11. [illegible]
12. [illegible]
13. [illegible]
14. [illegible]

Scanned by CamScanner

OPPO F5 Youth
Noida

पत्र संख्या : मु0अ0 (वि0)/नोएडा क्षेत्र/नोएडा /तद् दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक (तकनीकी), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।
2. अधीक्षण अभियंता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-द्वितीय, नोएडा।
3. अधीक्षण अभियंता, विद्युत परेषण मण्डल-द्वितीय, सेक्टर-20, नोएडा।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड-प्रथम, 220 केवी उपकेन्द्र, सेक्टर-20, नोएडा।
5. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-द्वितीय, नोएडा को उक्त प्रार्थना पत्र एवं अन्य प्रपत्र सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड-द्वितीय, नोएडा।
7. उपखण्ड अधिकारी, विद्युत नगरीय वितरण उपखण्ड-सप्तम, नोएडा।
8. तकनीकी सहायक, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-द्वितीय, नोएडा।

संलग्नक: यथोपरि।

(राकेश कुमार)
मुख्य अभियंता

पत्र संख्या : 1966 /तद् दिनाक : 25/7/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1- M/s CBS International Projects Pvt. Ltd., Plot No. 01, Sector-90, Noida, Distt. Gautam Budh Nagar.

(राकेश कुमार)
मुख्य अभियंता

Scanned by CamScanner

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2021/38972/GBN/GAUTAM BUDDH NAGAR/11505/DD
दिनांक: 19-10-2021

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **CBS INTERNATIONAL PROJECTS PVT LTD** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम)पता **PLOT NO-01,SECTOR-90,NOIDA** तहसील - **DADRI**, प्लाट एरिया **102949 sq.mt** , कुल कवर्ड एरिया **80023.71** (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - **2**जिसमें

ब्लॉक/टावर	**प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या**	**बेसमेन्ट की संख्या**	**ऊँचाई**
TOWER A	27	2	116 mt.
TOWER E	27	2	116 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **CBS INTERNATIONAL PROJECTS PVT LTD** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **05-11-2021** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **LALIT KUMAR SINGH-9350815745** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Business** के अन्तर्गत वैधता तिथि **10-11-2021** से **09-11-2024** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **CBS INTERNATIONAL PROJECTS PVT LTD** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **CBS INTERNATIONAL PROJECTS PVT LTD** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है | इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा | यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है |"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(उप निदेशक)

Digitally Signed By
(AMAN SHARMA)
[6F3173ACF1282848601D36130C6B4188B05EE040]
10-11-2021

निर्गत किये जाने का दिनांक : 10-11-2021
स्थान : MEERUT

विद्युत सुरक्षा निदेशालय

कार्यालय उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा,उत्तर प्रदेश शासन, गाजियाबाद रीजन,

F-6,(प्रथम तल), पटेलनगर-3, गाजियाबाद 201001

संख्या- 581 नि/ गाजियाबाद / विनियम 37(VI) / 2021-2022 दिनांक- 16-11-2021

विद्युत सुरक्षा निदेशालय का प्रमाणक
(Certificate of Electrical Safety Directorate)

विषय- "केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ती सम्बन्धी उपाय) विनियम "2010" के विनियम 37(VI) एवं उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2005 के क्लाज 4.4 (एनेक्जर 4.4) के अन्तर्गत मध्यम विभव विद्युत अधिष्ठापन का प्रारम्भिक निरीक्षण।

उपभोक्ता का नाम एवं पता- M/S CBS INTERNATIONAL PVT. LTD.
PLOT No. 1, SECTOR-90, NOIDA EXPRESSWAY, NOIDA
DISTRICT-GAUTAM BUDDHA NAGAR, U.P.

Details of Equipment – 12 No. Lift

Sr.no.	Make	Job No.	Tower	Capacity
1.	TOSHIBA	IOUP-0395-P-1	A	20 Passengers
2.	TOSHIBA	IOUP-0395-P-2	A	20 Passengers
3.	TOSHIBA	IOUP-0395-P-3	A	20 Passengers
4.	TOSHIBA	IOUP-0395-P-4	A	20 Passengers
5.	TOSHIBA	IOUP-0395-P-5	A	20 Passengers
6.	TOSHIBA	IOUP-0395-P-6	A	20 Passengers
7.	TOSHIBA	IOUP-0395-P-7	E	20 Passengers
8.	TOSHIBA	IOUP-0395-P-8	E	20 Passengers
9.	TOSHIBA	IOUP-0395-P-9	E	20 Passengers
10.	TOSHIBA	IOUP-0395-P-10	E	20 Passengers
11.	TOSHIBA	IOUP-0395-P-11	E	20 Passengers
12.	TOSHIBA	IOUP-0395-P-12	E	20 Passengers

निरीक्षण शुल्क रू0-18000.00 जो चालान सं0-KE00019, दिनांक-12.11.2021 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, राजनगर, गाजियाबाद में जमा किया गया।

प्रिय महोदय,

प्रमाणित किया जाता है कि इस निदेशालय के अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उपरोक्त विद्युत अधिष्ठापन का **दिनांक-15.11.2021** को निरीक्षण करने पर पाया गया कि विद्युत अधिष्ठापन "केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ती सम्बन्धी उपाय) विनियम 2010" के सम्बन्धित विनियमों के अन्तर्गत सन्तोषजनक है। अतः उपरोक्त **लिफ्ट** के विद्युत अधिष्ठापन को इस्तेमाल में लाये जानें में इस कार्यालय को आपत्ति नहीं है। **यह अनापत्ति प्रमाण पत्र 03 वर्ष के लिये मान्य है ।**

उपनिदेशक
विद्युत सुरक्षा उ०प्र० शासन
गाजियाबाद रीजन गाजियाबाद

विद्युत सुरक्षा निदेशालय (Electrical Safety Directorate)

U.P. Real Estate Regulatory Authority
Naveen Bhawan, Rajya NiyojanSansthan
Kalakankar House, Old Hyderabad, Lucknow - 226007

Order

No. 2789/Tech.Cell/Pr.Ex./2020-21 Date: 06, June, 2020

Subject: Regarding extension of registration of real estate projects due to *'force majeure'*under the provisions of Real Estate (Regulation and Development), Act 2016

The current spread of Coronavirus disease (COVID-19) has created a serious impact on the social and economic life not only in the State of Uttar Pradesh but for whole of the country and the world. Considering the situation created by the pandemic COVID-19 and consequent nation-wide lockdown w.e.f. 25th March 2020, reverse migration of labourers to their native places and break in supply chain of construction material adversely impacting the construction activities of real estate projects across the country, the Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, in consultation with all the stakeholders, has issued an advisory through its Office Memorandum No. O- 17024/230/2018- housing- UD/EFS- 9056405 dated 13th May 2020 regarding extension of registrations of real estate projects due to *'force majeure'* under the provisions of Real Estate (Regulation and Development), Act 2016 (RERA). The Government of India has advised as follows:-

- Section 6 of RERA, 2016 provides for 'extension of registration of real estate project' on account of *'force majeure'*, which includes any calamity caused by nature affecting the regular development of the real estate projects. It is quite evident that current pandemic caused by nature is adversely affecting regular development of real estate projects. Hence, it attracts invoking the provision of *'force majeure'*.

- In order to avoid submission of separate application for extension of each project and orders thereon, the Regulatory Authorities may, in pursuance of section 37 of RERA read with other enabling provisions, in their respective jurisdictions issue following orders/directions to the effect that 'notwithstanding anything contained to the contrary and by virtue of powers conferred under section 37 read with section 34(f) of the RERA, the registration or extension thereto under Section 5, 6, and 7(3) of the RERA or Rules thereunder, all registered projects under jurisdiction of Regulatory Authority for which the completion date or revised completion date or extended completion date as per registration expires on or after 25thMarch,2020':

  (i) Regulatory Authorities may issue suitable orders/ directions to extend the registration and completion date or revised completion date or extended completion date

automatically by 6 months due to outbreak of COV ID-19 (Corona Virus), which is a calamity caused by nature and is adversely affecting regular development of real estate projects by invoking force majeure clause;

(ii) Regulatory Authorities may, on their own discretion, consider to further extend the date of completion as per registration for another period upto 3 months, if the situation in their respective State or any part thereof, for reasons to be recorded in writing, needs special consideration of invoking *'force majeure'* in view of current pandemic;

(iii) Regulatory Authorities may issue fresh 'Project Registration Certificates' with revised timeline in each such registered real estate project at the earliest; and

(iv) Regulatory Authorities may extend concurrently the timelines of all statutory compliances in accordance with the provisions of RERA and the rules and regulations made thereunder.

In the wake of COVID-19 pandemic, the Authority has received representations from various organisations representing the real estate sector in the State viz. NAREDCO and CREDAI along with individual representations wherein they have explained in detail the issues being faced by the sector as a result of COVID-19 pandemic. Office bearers representing different organisations of the real estate sector and different promoters also raised their concerns in this regard in a meeting of promoters held by the Authority through video conferencing.

Therefore, considering all the aspects, having a detailed deliberation in this regard and also having in view the aforesaid advisory issued by Government of India, the Authority using the powers conferred on it under section 37 read with section 34 (F) of the RERA issues the following directions:-

1. **Extension of estimated end date and validity of registration**

(i) Notwithstanding anything contained to the contrary and by virtue of powers conferred under Section 37 read along with Section 34(f) of the RERA, the registration or extension thereto under Section 5,6,7(3) of the Real Estate (Regulation and Development)Act, 2016 or Rules 6 and 7 of the U.P. Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2016 thereunder, all registered projects under jurisdiction of U.P. RERA for which the completion date or revised completion date or extended completion date as per registration expires on or after 25th March, 2020, the registration and completion date or revised completion date or extended completion date, as the case may be, is hereby extended by 6 months due to outbreak of COVID-19 (Corona Virus) which is a calamity caused by nature and is adversely affecting regular development of real estate projects by invoking *force majeure*clause.

Provided that the project will not require an extension if the CC/OC of the project has already been obtained.

(ii) For the aforesaid extension, no fees will be charged from the promoters.

(iii) The Authority will soon issue fresh 'Project Registration Certificates' with revised timeline in each such registered real estate project.

2. Extension of time for statutory Compliances

The time limit for various compliances (including any of the previous Quarterly Progress Reports and Annual Audit Reports of projects) under the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016, the U.P. Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2016, or under U.P. Real Estate Regulatory Authority (General) Regulations, 2019 and the Orders of the Authority, which were due to be made by 31.03.2020, is hereby extended upto 30th June,2020, on the ground of *force majeure*.

For the aforesaid extension of time-limit for submission of any of the previous QPRs and Annual Audit Reports, the late fee as prescribed in Office Memorandum No. 3206/ U.P.-RERA/Pari. Panjee./ 2019-20 Dated 10th April, 2019 is hereby waived as a onetime measure provided the promoter fills and submits all such reports by 30th June, 2020.

The directions, issued as above, shall come into force immediately.

(Abrar Ahmed)
Secretary

Copy forwarded to the following for information and necessary action at their end

1. Hon'ble Chairman, U.P. RERA.
2. All the hon'ble members, U.P. RERA
3. Principal Secretary, Housing and Urban Planning, Government of Uttar Pradesh.
4. Principal Secretary, Industrial Development, Government of Uttar Pradesh.
5. All the competent authorities, Uttar Pradesh.
6. Adjudicating officers, U.P. RERA
7. All the officers, U.P. RERA,
8. A.D. (Systems), U.P. RERA for uploading the order on the web portal of UP RERA.
9. Project Management Unit, U.P. RERA
10. All the promoters of the projects registered with U.P. RERA

6/6/20

(Abrar Ahmed)
Secretary

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस,
ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ–226007

पत्रांकः 8208/यू.पी. रेरा/20वीं बैठक/का0आ0/2019–20 दिनांकः 16 सितम्बर, 2019

कार्यालय आदेश

1– रेरा अधिनियम की धारा–11 (4)(b) में यह प्राविधान है कि "The promoter shall be responsible to obtain the completion certificate or the occupancy certificate, or both, as applicable, from the relevant competent authority as per local laws or other laws for the time being in force and to make it available to the allottees individually or to the association of allottees, as the case may be." आशय यह है कि पूर्णता प्रमाण–पत्र या अधिभोग प्रमाण–पत्र स्थानीय विधियों के अन्तर्गत प्राप्त किया जाएगा।

2– उ0 प्र0 अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेन्ट ऐक्ट के चैप्टर V, धारा–15–A में प्राविधान है कि "**(15-A Completion Certificat-(1)** Every person or body having been granted permission under sub-section (3) of section 15, shall complete the development according to the approved plan and send a notice in writing of such completion to the Authority, and obtained a completion certificate from the Authority in the manner prescribed or provided in the bye-laws of the Authority.

Provided that if completion certificate is not granted and refusal to grant it is not intimated within three months after receipt of the notice of completion, it shall be deemed that the completion certificate has been granted by the Authority."

3– आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–1241/8–3–17/34विविध/2008 दिनांक 31–10–2017 के प्रस्तर–2 में यह कहा गया है कि :–

" उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम–1973 की धारा–57 के अधीन AMRUT योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी मॉडल बिल्डिंग बाईलाज–2016 तथा Ease of Doing Business के अन्तर्गत भारत सरकार के Business Reform Action Plan 2017 की अपेक्षाओं एवं उक्त के कार्यान्वयन हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) में संलग्नक के अनुसार सम्यक विचारोपरान्त संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है।"

4– शासनादेश संख्या 1241/8/3/17/34 विविध/2008 दिनांक 31–10–2017 के संलग्नक में प्रस्तर–6 के अन्तर्गत निम्नवत प्राविधान कर दिया गया है:–

"पूर्णता प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन प्राप्त होने पर अधिकतम सात कार्य–दिवस में जॉच/परीक्षण कर स्वीकृत अथवा शमनित मानचित्र के अनुरूप मौके पर विकास/निर्माण न पाए जाने की स्थिति में उपाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन को अस्वीकार करते हुए अपेक्षित संशोधनों सहित आवेदन को आवेदन करने के 08 कार्य–दिवस में सूचित कर दिया जायेगा।

ऐसा न करने की दशा में प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण–पत्र स्वीकृत किया (डीम्ड एप्रूव्ड) माना जायेगा।"

5– वर्तमान में प्रभावी उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा–57 के अधीन अधिसूचित बिल्डिंग बायलाज के अनुसार पूर्णता प्रमाण–पत्र के आवेदन को अस्वीकार करने के लिए 07 कार्यदिवस की सीमा निर्धारित है और यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा 08 कार्यदिवस के अन्दर आवेदक को आवेदन अस्वीकार करने की सूचना नहीं दी जाती, तो ऐसी दशा में प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण–पत्र स्वीकृत किया जाना (डीम्ड एप्रूव्ड) माना जाएगा।

6– उ0प्र0 भू–सम्पदा (विनियम एवं विकास) नियमावली 2016 के नियम–2 (1)(h)(iv) में यह व्यवस्था निर्धारित की गयी है कि यदि किसी परियोजना में विकास कार्य पूरे कर लिए गए हैं और पूर्णता प्रमाण–पत्र के लिए सक्षम प्राधिकारी से आवेदन कर लिया गया है, तो ऐसी परियोजना को रेरा में पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इस नियम का आशय यह है कि इस प्रकार की परियोजनाओं में प्रोमोटर द्वारा आवंटी को रजिस्टर्ड सेल/लीज़/सबलीज़ डीड निष्पादित करके कब्जा दिया जा सकेगा और आवंटी द्वारा कब्जा प्राप्त किया जा सकेगा।

अतः आवंटियों के हितों के संरक्षण तथा रेरा अधिनियम एवं नियमावली में आवंटियों को उन्हें आवंटित इकाईयों का कब्जा सुलभ करवाने के उद्धेश्यों के पूर्ति हेतु उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 04.09.2019 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक में सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिया गया :–

1– यदि प्रोमोटर द्वारा विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, सीवरेज निस्तारण, जल निकासी तथा आन्तरिक मार्गों से सम्बन्धित कार्यों को पूर्ण करके 1– इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टीफिकेट, 2–फायर सेफ्टी सर्टीफिकेट, 3–स्ट्रक्चरल इंजीनियर सर्टीफिकेट तथा 4–लिफ्ट इन्स्टालेशन/सेफ्टी सर्टीफिकेट सहित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पूर्णता प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रोमोटर के आवेदन–पत्र को 7 कार्य दिवस में अस्वीकार करते हुए अपेक्षित संशोधनों सहित आवेदक को 8 कार्यदिवस के अन्दर सूचित नहीं किया गया है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा पूर्णता प्रमाण–पत्र स्वीकृत किया (डीम्ड अप्रूव्ड) माना जाएगा।

2– ऐसी दशा में प्राधिकरण द्वारा प्रोमोटर को यह आदेश दिया जा सकेगा कि उनके द्वारा रजिस्ट्रर्ड सेल डीड/लीज़ डीड/सब लीज़ डीड निष्पादित करके आवंटी को कब्जा दिया जाए, और इसी प्रकार आवंटी को भी आदेश दिया जा सकेगा कि उनके द्वारा रजिस्ट्रर्ड सेल डीड/लीज़ डीड/सब लीज़ डीड निष्पादित कराकर कब्जा प्राप्त कर लिया जाए। नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना एक्सप्रेस वे जैसे प्राधिकरणों में, जहां पर ट्राई पारटाइट सबलीज़ डीड निष्पादित करने की व्यवस्था है, वहां पर प्रोमोटर द्वारा रजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट फार सेल निष्पादित करके आवंटी को आवंटित यूनिट का कब्जा दिया जा सकेगा।

3– उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के आदेशों के कार्यान्वयन में भी इसी व्यवस्था का अनुपालन किया जाएगा।

सर्वसम्बन्धित द्वारा प्राधिकरण के इन निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

16/9/19

(अबरार अहमद)
सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मा0 अध्यक्ष, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को सूचनार्थ कृपया।
2. समस्त मा0 सदस्य, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को सूचनार्थ कृपया।
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ.प्र. शासन।
4. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
5. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथॉरिटी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथॉरिटी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस–वे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथॉरिटी।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ.प्र. औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
8. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण गोरखपुर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, भदौहीं, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सतहरिया जौनपुर।
9. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त प्रमोटर्स को उ.प्र. रेरा की वेबसाइट पर प्रकाशन के माध्यम से तथा उनकी लॉगिन के माध्यम से अनुपालनार्थ।
11. समस्त होम बायर्स एसोसिएशन तथा होम बायर्स को उ.प्र. रेरा की वेबसाइट पर प्रकाशन के माध्यम से सूचनार्थ।
12. तकनीकी सलाहकार, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण लखनऊ।
13. संयुक्त सचिव, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ।
14. उप सचिव, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा।
15. सहायक निदेशक सिस्टम, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।

16/9/19

(अबरार अहमद)
सचिव

जामिया मिल्लिया इस्लामिया
(संसदीय अधिनियमानुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग, नई दिल्ली–110025
JAMIA MILLIA ISLAMIA
NAAC Accredited 'A' Grade
(A Central University by an Act of Parliament)
Maulana Mohammad Ali Jauhar Marg, New Delhi-110025

Phone (Office) : 011-26985227
26981717 (Ex 2312)
Phone (Personal) : 9810984903
26981717 (Ex 2318)
Email : kmoin_ci@hotmail.com
kmoin@jmi.ac.in
Website : www.jmi.ac.in

جامعہ ملیہ اسلامیہ

सिविल इंजीनियरिंग विभाग
इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संकाय
Department of Civil Engineering
Faculty of Engineering & Technology

Ref. No. 2021/4416

Dated:- 15.11.2021

Subject: Proof checking of structural drawings and design of **EXISTING INDUSTRIAL/ IT- ITES BUILDING'** at Plot No. 1, Sector 90 Noida for --- for **M/s C B S International Projects Pvt. Ltd.**

This is to certify that the structural drawings & design submitted by Vintech Consultants, Plot No C-35, Pamposh Enclave, G.K.-1, New Delhi-110048 for **EXISTING INDUSTRIAL/ IT- ITES BUILDING'** at Plot No. 1, Sector 90 Noida**,** as per details shown in **Annexure 1** has been checked and found to be conforming to relevant Codes of practice as per the latest Indian Standards. All the stipulated combination of loads (static and dynamic) in vertical and lateral direction has been incorporated in the analysis and design. The design and drawings have been checked and found to be satisfactory for Seismic Zone IV. Hence they are approved.

The responsibility of the Jamia Millia Islamia shall be limited to proof checking of the structural design calculations and drawings only. All procedural/ operational matters and architectural/ functional details will be the responsibility of the owner/owners.

Dr. Khalid Moin
(Professor)

Dr. KHALID MOIN
Professor
Deptt. of Civil Engineering
F/O Engineering & Technology
Jamia Millia Islamia
New Delhi-110025

Scanned with CamScanner

ANNEXURE 1

Ref. No. 2021/4416 Dated:- 15.11.2021

Plot Area 1,02,949.00 sqm
Total Built-up Area 1,43,899.400 sqm

S. No	Floor	Tower A & E Built Up Area in Sqm
1	Ground Floor	3338.57
2	Upper Ground Floor	3326.24
3	2nd Floor	3238.02
4	3rd Floor	3238.02
5	4th Floor	3238.02
6	5th Floor	3238.02
7	6th Floor	3238.02
8	7th Floor	3238.02
9	8th Floor	3238.02
10	9th Floor	3238.02
11	10th Floor	3238.02
12	11th Floor	3238.02
13	Service Floor 1	3238.02
14	12th Floor	3238.02
15	14th Floor	3238.02
16	15th Floor	3238.02
17	16th Floor	3238.02
18	17th Floor	3238.02
19	18th Floor	3238.02
20	19th Floor	3238.02
21	20th Floor	3238.02
22	21st Floor	3238.02
23	22nd Floor	3238.02
24	23rd Floor	3238.02
25	24th Floor	3238.02
26	25th Floor	3238.02
27	26th Floor	3238.02
28	27th Floor	3238.02
29	Service Floor 2	3238.02
30	Terrace Floor	702.58
31	Mumty/Connection Bridge/Machine Room/Water Tank	785.40
32	Basement 1	24106.55
33	Basement 2	24213.53
Total Covered Area 1,43,899.400 Sqm		

Dr. Khalid Moin
(Professor)

Dr. KHALID MOIN
Professor
Deptt. of Civil Engineering
F/O Engineering & Technology
Jamia Millia Islamia
New Delhi-110025

Scanned with CamScanner

W1 Noida Authority Completion Paymen...

Customer Invoice

Invoice: #2111[illegible]
Transactionid: #c551[illegible]
Date: 11/26/2021 1:22:05 PM

Company Detail

- NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY
- Main Administrative Building
- Sector- 6, Noida-201301, Uttar Pradesh
- Online Completion Certificate System
- GST No. 09AAALN0120A1ZV
- Web : www.completion.noidaauthorityonline.com

Customer Details

- Name: CBS international projects pvt ltd
- Mobile: 9717290936
- Email id :ratishpathania@gmail.com
- Address: Plot no-01, sector 90 Noida
- GST :09AADCC0446Q1ZC
- Site Address NA / 01 /90 / Plot no-01, sector 90 Noida
- Category : Industrial Plot

Extra Information

Taxable Fee : Rs. 787333.50
SGST (9%) : Rs. 70860.02
CGST (9%): Rs. 70860.02
Total Processing Fee : Rs. 929053.53

Completion fees is chargeable as per New Okhla Industrial Development Authority Completion By Laws i.e. 10 Rs./ sq. m.

Layout Fees is chargeable as per New Okhla Industrial Development Area Building Regulation 2010.

This is a system generated document and does not require signature. Any unauthorized use, disclosure, dissemination, or copying of this document is strictly prohibited and may be unlawful. Thank you. Please quote this receipt no. for any